

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3100
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्यायालय

3100. श्री पुट्टा महेश कुमार :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर एलुरु जिले सहित देश भर के न्यायालयों में लंबित सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभाजन के बाद बने जिलों में नए जिला न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस हेतु आबंटित और उपयोग की गई धनराशि और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) देश भर के विभिन्न न्यायालयों, विशेषकर से आंध्र प्रदेश के न्यायालयों में रिक्तियों की कुल संख्या और उनमें कमी लाने के लिए राज्य-वार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन प्रमुख मुद्दों की पहचान की है, जिनके कारण देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

भारत का उच्चतम न्यायालय	वर्ष	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल	दांडिक	योग
	2020	52290	12796	65086
	2021	55973	14266	70239
	2022	54940	14828	69768
	2023 *	55015	14496	69511
	2024 **	64300	18277	82577

*(01.02.2023 तक),**(10.12.2024 तक)

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान एलुरु जिले में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या		
	सिविल	दांडिक	योग
2020	28026	22214	50240
2021	32645	28823	61468

2022	30704	32848	63552
2023	29937	35601	65538
2024 *	29253	36595	65848

*31.10.2024 तक

(ख) और (ग) : जिला और अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायालयों की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उच्च न्यायालय के मामले में, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2000/379 का में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात पीठों की स्थापना की जाती है। मई, 2014 से, राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया है।

न्यायिक अवसंरचना केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि सहभाजन में वित्तीय सहायता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका के विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अधीन, पांच घटकों अर्थात् न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है। इस संबंध में, 1993-94 से इस स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश को 272.2395 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। आज की तारीख तक, आंध्र प्रदेश में 648 न्यायालय हॉल और 600 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में 84 न्यायालय हॉल और 16 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

(घ) : तारीख 10.12.2024 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में एक (1) रिक्ति है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों की राज्यवार संख्या क्रमशः **उपाबंध-3 और उपाबंध-4 पर दी गई है।**

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि विद्वमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उदभूत होती रहती हैं।

एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। एमओपी के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकार के अभिमत भी प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार करना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक कार्य ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समयसीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

(ङ) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा करना न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान हेतु पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके प्रणाली में विलंब और बकाया मामलों को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करने के दो उद्देश्य थे। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचनात्मक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय तथा मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना अन्तर्वर्लित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के संनिर्माण के लिए निधियाँ जारी की जा रही हैं, जिससे मुकदमेबाजों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन सरल हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिल सके। वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 11571.57 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, न्यायालय

कक्षों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.10.2024 तक 23,590 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.10.2024 तक 21,076 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण 1 और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारीख 30.09.2024 तक, जिला न्यायालयों में 1375 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 28 ई-सेवा केंद्र वकीलों और मुकदमेबाजों को सिविल केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण-III मंजूरी दे दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 767 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
09.12.2024	25,741	20,479

हालाँकि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान, में जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है; इन मामलों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामले भी हैं। तारीख 30.09.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध आदि के मामलों पर कार्रवाई के लिए 862 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े दाण्डिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। तारीख 30.09.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 अनन्य पॉक्सो (ईपीओसीओ) न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 2,81,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न विधियों, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन समयसीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में शीघ्रता लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2015 द्वारा किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों की संख्या के चरण में अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या पूर्व मुकदमेबाजी के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिग्री मानी जाती है और यह अंतिम होती है तथा सभी पक्षों पर आबद्धकर होती है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतों सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख को आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	पूर्व मुकदमा मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
कुल	17,38,89,774	4,34,36,355	21,73,26,129

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

प्रवर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्यौरे	दी गई सलाह	% वार ब्यौरे
लिंग के अनुसार				
महिला	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19
अन्य पिछड़ा वर्ग	3252495	31.69	3213067	31.67
अनुसूचित जाति	3246025	31.63	3215657	31.68
अनुसूचित जनजाति	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	10262591		10146785	

*डाटा 31-10-2024 तक.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित मामलों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण।

क्रम सं.	राज्य	31.12.2020 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2022 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2023 तक लंबित मामलों की संख्या			10.12.2024 तक लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	347979	287241	635220	412688	361264	773952	414050	415097	829147	422382	442563	864945	430694	469201	899895
2	तेलंगाना	284531	389770	674301	330160	475462	805622	421679	637722	1059401	349414	568181	917595	333244	599004	932248
3	अंदमान और निकोबार द्वीप			0			0	3176	8710	11886	3731	5036	8767	3811	4276	8087
4	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1174	2975	4149	1953	8256	10209
5	असम	79395	277802	357197	86204	331584	417788	93994	394806	488800	101120	352416	453536	105037	397676	502713
6	बिहार	429316	2728754	3158070	476437	2902792	3379229	508954	2936205	3445159	537060	3051832	3588892	534055	3076751	3610806
7	चंडीगढ़	21004	36414	57418	22970	46532	69502	23229	56297	79526	23347	125067	148414	23284	82273	105557
8	छत्तीसगढ़	59709	264564	324273	68905	307315	376220	75569	336030	411599	78493	332086	410579	79471	379231	458702
9	दिल्ली	216432	739418	955850	241138	841277	1082415	247208	1046363	1293571	230685	993588	1224273	220208	1302747	1522955
10	दादर एवं नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	2953	3326	6279	3147	3412	6559	3218	3453	6671	3441	3883	7324	3423	4316	7739
11	गोवा	23822	32723	56545	25811	33559	59370	25821	30554	56375	26211	30967	57178	26739	32312	59051
12	गुजरात	457897	1432770	1890667	457921	1493629	1951550	424744	1318979	1743723	372162	1217306	1589468	350389	1316006	1666395
13	हरियाणा	386383	714521	1100904	433043	848654	1281697	454453	1003817	1458270	459885	973156	1433041	438526	993105	1431631
14	हिमाचल प्रदेश	145240	271324	416564	154753	301196	455949	154316	321821	476137	164325	409285	573610	169263	486831	656094
15	जम्मू-कश्मीर	85913	129890	215803	95828	147198	243026	98331	201385	299716	101210	188996	290206	108271	225052	333323
16	झारखंड	77284	361283	438567	89806	405302	495108	90175	428981	519156	91346	451630	542976	91856	455071	546927
17	कर्नाटक	841009	905877	1746886	867552	955551	1823103	910317	982948	1893265	942582	998989	1941571	998446	1203858	2202304
18	केरल	481685	1316657	1798342	516610	1426645	1943255	517038	1416325	1933363	518099	1312818	1830917	517326	1219750	1737076
19	लद्दाख	366	383	749	398	426	824	657	497	1154	631	697	1328	694	762	1456
20	मध्य प्रदेश	352554	1337499	1690053	379592	1496602	1876194	393250	1607018	2000268	394159	1610411	2004570	413371	1618815	2032186
21	महाराष्ट्र	1354707	3161604	4516311	1487070	3394648	4881718	1567297	3415614	4982911	1637874	3562441	5200315	1697480	3788061	5485541
22	मणिपुर	6851	3943	10794	8440	4362	12802	7994	4275	12269	8705	4365	13070	8460	4201	12661
23	मेघालय	2793	7610	10403	4300	10322	14622	4563	11572	16135	4508	11706	16214	4300	10930	15230
24	मिजोरम	1650	3049	4699	2174	3708	5882	2320	2822	5142	2464	3102	5566	3023	2467	5490

25	नगालैंड	161	1378	1539	493	2110	2603	576	2390	2966	675	2159	2834	695	2082	2777
26	उड़ीसा	282943	1099595	1382538	303218	1215888	1519106	302763	1256575	1559338	293052	1319143	1612195	273786	1380777	1654563
27	पुडुचेरी			0	14446	19583	34029	11881	17950	29831	12896	21183	34079	13012	22374	35386
28	पंजाब	348144	466394	814538	394728	524130	918858	401902	520458	922360	378545	472637	851182	378067	491756	869823
29	राजस्थान	485531	1344931	1830462	518034	1511780	2029814	524351	1599124	2123475	537184	1773804	2310988	479940	1869413	2349353
30	सिक्किम	571	999	1570	735	1191	1926	666	1177	1843	626	1038	1664	799	956	1755
31	तमिलनाडु	722201	566372	1288573	757785	606132	1363917	751131	681444	1432575	725902	723103	1449005	736752	787101	1523853
32	त्रिपुरा	9119	31913	41032	9138	30066	39204	11282	28730	40012	11759	33620	45379	12405	37463	49868
33	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	390	527
34	उत्तर प्रदेश	1854778	6717314	8572092	1912283	7909941	9822224	1857096	9116384	10973480	1875023	9751773	11626796	1827129	9924780	11751909
35	उत्तराखंड	41825	218739	260564	44272	256729	301001	44847	282503	327350	44930	313102	358032	46430	315317	361747
36	पश्चिमी बंगाल	548795	1831838	2380633	605904	1984089	2589993	614648	2157642	2772290	620769	2368053	2988822	46430	315317	361747
कुल		9953541	26685895	36639436	10725983	29853079	40579062	10963496	32245668	43209164	10976369	33433111	44409480	10378906	32828678	43207584

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

‘आंध्र प्रदेश में न्यायालय’ के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण।

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	31.12.2020 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2022 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2023 तक लंबित मामलों की संख्या			10.12.2024 तक लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल
1	इलाहाबाद	415029	358379	773408	418874	384693	803567	556215	476013	1032228	568387	508167	1076554	599544	538945	1138489
2	बंबई	471321	87798	559119	472580	96438	569018	506774	103960	610734	596154	116276	712430	539677	111717	651394
3	कलकत्ता	225783	41648	267431	190612	34837	225449	178268	29630	207898	168530	26849	195379	176542	28413	204955
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	42030	9871	51901	44786	10863	55649	46628	11873	58501	48308	14133	62441	48138	16183	64321
5	तेलंगाना	203093	33759	236852	220805	35713	256518	219891	34198	254089	218291	30096	248387	212660	31363	244023
6	आंध्र प्रदेश	177061	30701	207762	189934	32908	222842	204907	35331	240238	212152	37491	249643	208471	38728	247199
7	छत्तीसगढ़	47219	28617	75836	51496	29505	81001	58969	32215	91184	58525	31938	90463	55236	29087	84323
8	दिल्ली	65654	25541	91195	73132	26936	100068	75350	29921	105271	90696	37426	128122	90885	36349	127234
9	गुजरात	97226	45577	142803	101465	50665	152130	105891	56038	161929	112117	56931	169048	116159	54932	171091
10	हिमाचल प्रदेश	64625	9237	73862	72084	10154	82238	79041	12169	91210	85437	14108	99545	81449	12167	93616
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	55565	7903	63468	40982	6779	47761	36921	7605	44526	36002	8241	44243	36897	8533	45430
12	झारखंड	41240	47205	88445	42300	46071	88371	39234	48758	87992	38519	47271	85790	33005	41737	74742
13	कर्नाटक	250805	42454	293259	225693	40253	265946	255999	48445	304444	240721	48168	288889	248380	52142	300522
14	केरल	169948	44436	214384	169527	42998	212525	157415	39899	197314	201179	54099	255278	198897	51544	250441
15	मध्य प्रदेश	223105	139827	362932	256719	156748	413467	265629	164114	429743	269662	176686	446348	278676	189347	468023
16	मणिपुर	3962	412	4374	4327	490	4817	4404	461	4865	4120	511	4631	4591	649	5240
17	मेघालय	1328	115	1443	1367	211	1578	1044	144	1188	901	224	1125	920	264	1184
18	पंजाब और हरियाणा	372991	264157	637148	282851	164839	447690	279794	168092	447886	275684	165386	441070	268349	163438	431787
19	राजस्थान	387923	135677	523600	422566	151498	574064	465873	167914	633787	490824	181369	672193	477897	179600	657497
20	सिक्किम	204	37	241	146	34	180	135	30	165	126	53	179	144	66	210
21	त्रिपुरा	2044	303	2347	1549	187	1736	1444	157	1601	1124	151	1275	818	155	973

22	उत्तराखंड	23418	15258	38676	24255	17667	41922	25848	19175	45023	28152	22380	50532	30265	24829	55094
23	मद्रास	518985	61785	580770	521391	58351	579742	495771	54312	550083	484616	58084	542700	458729	57278	516007
24	उड़ीसा	119076	53400	172476	142821	52340	195161	122027	42682	164709	109964	38483	148447	108339	37234	145573
25	पटना	97229	81606	178835	113172	112456	225628	111517	100589	212106	109101	88562	197663	105924	95188	201112
कुल		4076864	1565703	5642567	4085434	1563634	5649068	4294989	1683725	5978714	4449292	1763083	6212375	4380592	1799888	6180480

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड (एनजेडीजी)।

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों का विवरण (09.12.2024 तक)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	79
2	आंध्र प्रदेश	37	8
3	बंबई	94	27
4	कलकत्ता	72	29
5	छत्तीसगढ़	22	6
6	दिल्ली	60	25
7	गुवाहाटी	30	6
8	गुजरात	52	20
9	हिमाचल प्रदेश	17	6
10	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख	25	10
11	झारखंड	25	7
12	कर्नाटक	62	12
१३	केरल	47	2
14	मध्य प्रदेश	53	18
15	मद्रास	75	9
16	मणिपुर	5	1
17	मेघालय	4	0
18	उड़ीसा	33	14
19	पटना	53	18
20	पंजाब और हरियाणा	85	33
21	राजस्थान	50	18
22	सिक्किम	3	0
23	तेलंगाना	42	15
24	त्रिपुरा	5	0
25	उत्तराखंड	11	5
	कुल	1122	368

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

09.12.2024 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	623	564	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	33	11
3.	असम	485	461	24
4.	बिहार	2019	1536	483
5.	चंडीगढ़	30	30	0

6.	छत्तीसगढ़	663	465	198
7.	दादर और नागर हवेली तथा दमण और दीव	7	6	1
8.	दिल्ली	897	803	94
9.	गोवा	50	40	10
10.	गुजरात	1720	1185	535
11.	हरियाणा	781	552	229
12.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
13.	जम्मू-कश्मीर	322	276	46
14.	झारखंड	705	506	199
15.	कर्नाटक	1375	1156	219
16.	केरल	611	534	77
17.	लद्दाख	17	11	6
18.	लक्षद्वीप	4	4	0
19.	मध्य प्रदेश	2028	1691	337
20.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
21.	मणिपुर	62	49	१३
22.	मेघालय	99	56	43
23.	मिजोरम	74	45	29
24.	नगालैंड	34	24	10
25.	ओडिशा	1041	841	200
26.	पुडुचेरी	36	26	10
27.	पंजाब	804	723	81
28.	राजस्थान	1641	1313	328
29.	सिक्किम	35	23	12
30.	तमिलनाडु	1369	1023	346
31.	तेलंगाना	560	445	115
32.	त्रिपुरा	133	109	24
33.	उत्तर प्रदेश	3700	2704	996
34.	उत्तराखंड	298	270	28
35.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1105	875	230
36.	पश्चिमी बंगाल			
कुल		25741	20479	5262

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

* संघ राज्य क्षेत्र अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के सामने दर्शाया गया है।
